

प्रेषक,

अपर सचिव,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग/
विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग,
देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ

देहरादून: दिनांक: 14 जुलाई, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए आय-व्यय की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 261/XXXVI(3)/2017/42(1)2017 दिनांक 15 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या 04, लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-800-अन्य व्यय-03 राज्य विधि आयोग के हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक प्राविधान ₹70,00,000.00 मात्र (₹ सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष आवश्यकता के आधार पर कुल ₹10,00,000.00 मात्र (₹ दस लाख मात्र) का आय-व्ययक संलग्न अलोटमेंट आई0डी0 संख्या SI707040059 दिनांक 06 जुलाई, 2017 में दिये गये विवरणानुसार निम्न शर्त के साथ आवंटित करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध कराई जा रही है कि इस मद के अन्तर्गत प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय एवं न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।
2. पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय हो करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

5. उक्त सभी मदों में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. उक्त धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।
7. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012, शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017, शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. स्वीकृत आय-व्यय को आवश्यकतानुसार शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऑन लाईन अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों के निर्वतन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अनुदान संख्या 04, लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-800-अन्य व्यय-03 राज्य विधि आयोग के अन्तर्गत 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(भारत भूषण पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या - 320/XXXVI(3)/2017-18/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग 5, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, डाटा सेन्टर, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(भारत भूषण पाण्डेय)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017-2018

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (S058)

टन पत्र संख्या - .

नुदान संख्या - 004

अलोटमेंट आई डी - S1707040059

आवंटन पत्र दिनांक 06-Jul-2017

HOD Name - Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (4663)

| | | |
|----------------|----------------------|------|
| 1: लेखा शीर्षक | 2014 - न्याय प्रशासन | 00 - |
| | 800 - अन्य व्यय | |
| | 03 - राज्य विधि आयोग | |
| | 00 - राज्य विधि आयोग | |

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा | 0 | 1000000 | 1000000 |
| | 0 | 1000000 | 1000000 |

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1000000

(भारत कृष्णमोहन)
अपर सचिव,
विधायी एवं संसदीय कार्य
उत्तराखण्ड शासन।